

## लैंगिक संवेदनशीलता : चुनौतियाँ एवं पहल

डॉ कुमारी माधवी

अतिथि प्राध्यापिका, गृह विज्ञान विभाग

वीमेंस कॉलेज, समस्तीपुर

(एल एन एम यू, दरभंगा)

### परिचय

आधुनिक समाज में लैंगिक संवेदनशीलता एक ऐसी रोशनी है जो हर इंसान की छिपी हुई क्षमताओं को उजागर करती है। यह सिर्फ पुरुष और महिला के बीच की दीवारें नहीं तोड़ती, बल्कि ट्रांसजेंडर, नॉन-बाइनरी और अन्य लैंगिक पहचानों वाले लोगों को भी सम्मान की छाँव देती है, ताकि हर कोई बिना डर के अपनी पहचान जी सके। कल्पना कीजिए एक कक्षा जहाँ एक लड़की रोबोटिक्स का मॉडल बना रही है, लेकिन सहपाठी चिढ़ाते हैं कि "ये तो लड़कों का खेल है"। या एक ट्रांसजेंडर छात्र जो अपना असली नाम बताने से कतराता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई समझेगा नहीं। ऐसी छोटी-छोटी घटनाएँ हमारे दिल को छूती हैं और बताती हैं कि लैंगिक संवेदनशीलता कोई किताबी शब्द नहीं, बल्कि जीवंत भावना है जो गरिमा, सपनों और समानता की रक्षा करती है। शिक्षा जगत में, खासकर उच्च शिक्षा संस्थानों में, यह संवेदनशीलता छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच एक स्वस्थ, प्रेरणादायक माहौल बनाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स चेतावनी देती हैं कि लैंगिक असमानता वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य को चोट पहुँचाती है, उत्पादकता घटाती है और सामाजिक न्याय को कमजोर करती है। करोड़ों लोग अवसाद, तनाव और अवसरों की कमी से जूझते हैं, सिर्फ इसलिए कि समाज उन्हें उनकी लैंगिक पहचान के आधार पर जज करता है।

भारत जैसे विकासशील देश में यह चुनौती और गहरी हो जाती है। एक तरफ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, जहाँ नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ पितृसत्तात्मक सोच और पारंपरिक मान्यताएँ जो लड़कियों को घरेलू दायरे तक सीमित रखती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2021) के अनुसार, हर चौथी महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर लड़कों से दोगुनी है। उच्च शिक्षा कैंपसों में यौन उत्पीड़न की खबरें हमें झकझोरती हैं, UGC की साक्षम रिपोर्ट (2013) बताती है कि 60% से अधिक छात्राएँ खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। यह लेख लैंगिक संवेदनशीलता की इन चुनौतियों का गहराई से विश्लेषण करेगा और प्रभावी पहलों पर रोशनी डालेगा, ताकि शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए। आखिरकार, जब हम संवेदनशील बनेंगे, तभी एक समावेशी, न्यायपूर्ण समाज का सपना साकार होगा, जहाँ हर इंसान अपनी पूरी ऊँचाई तक उड़ सके।

**मुख्य शब्द** :-संवेदनशीलता, समावेशी, धारणाएँ, पितृसत्तात्मक, लैंगिक, प्रशासनिक।

### लैंगिक संवेदनशीलता की अवधारणा

लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ है लिंग-आधारित पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों और भेदभाव को पहचानना तथा उन्हें दूर करना। यह जैविक लिंग से अलग लैंगिक भूमिकाओं (Gender Roles) पर केंद्रित है, जो सामाजिक निर्माण हैं। उदाहरणस्वरूप, लड़कियों को घरेलू कार्यों तक सीमित रखने की धारणा या पुरुषों को भावनाओं को दबाने की अपेक्षा लैंगिक असंवेदनशीलता के उदाहरण हैं। शिक्षा में यह संवेदनशीलता पाठ्यक्रम, कक्षा चर्चा, खेलकूद और प्रशासनिक नीतियों में समावेशी भाषा और व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। यूनेस्को की 2020 रिपोर्ट के अनुसार, लैंगिक संवेदनशील शिक्षा से छात्राओं की भागीदारी 20-30% तक बढ़ सकती है।

### प्रमुख चुनौतियाँ

लैंगिक संवेदनशीलता को लागू करने में कई बाधाएँ आती हैं, जो सांस्कृतिक, संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर विद्यमान हैं :-

#### 1. सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़ियाँ

लैंगिक संवेदनशीलता लागू करने में सबसे बड़ी बाधा गहरी जड़ें जमाए बैठी सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़ियाँ हैं। भारतीय समाज में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग भूमिकाएँ सदियों से निर्धारित हैं। लड़कों को मजबूत, निर्णय लेने वाला और कमाने वाला माना जाता है, जबकि लड़कियों को कोमल, आज्ञाकारी और घर संभालने वाली। ये धारणाएँ परिवार, रिश्तेदारों, मीडिया और धार्मिक व्याख्याओं से लगातार मजबूत होती रहती हैं। इन रूढ़ियों के कारण लैंगिक समानता की बात को अक्सर "परंपरा के खिलाफ" या "पश्चिमी विचार" कहा जाता है, जिससे लोग बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। पितृसत्तात्मक संरचना में पुरुषों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, इसलिए वे बदलाव का विरोध करते हैं क्योंकि इससे उनका वर्चस्व कम हो सकता है। महिलाएँ भी कई बार इन्हीं रूढ़ियों को आंतरिक रूप से स्वीकार कर लेती हैं और नई पीढ़ी को वही सिखाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और गहरी है जहाँ लड़कियों की शिक्षा, खेलकूद और करियर को अभी भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। शहरी मध्यम वर्ग में भी "लड़कियाँ देर रात बाहर नहीं रहती" या "विज्ञान की बजाय आर्ट्स लो" जैसे नियम आम हैं।

मीडिया और विज्ञानों में महिलाओं को मुख्यतः सौंदर्य और घरेलू भूमिका में दिखाया जाता है, जिससे रूढ़ियाँ और पुख्ता होती हैं। नतीजतन, लैंगिक संवेदनशीलता की ट्रेनिंग या नीतियाँ लागू करने पर लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं होते और इन्हें केवल कागजी औपचारिकता मानते हैं। जब तक ये सांस्कृतिक मान्यताएँ नहीं बदलेंगी, कोई भी संस्थागत प्रयास आंशिक सफलता ही पा सकेगा।

## 2. शिक्षा संस्थानों में भेदभाव

शिक्षा संस्थानों में लैंगिक संवेदनशीलता लागू करने में संस्थागत भेदभाव एक बड़ी बाधा है। स्कूल-कॉलेजों में शिक्षक, प्रशासन और पाठ्यपुस्तकें अक्सर लैंगिक रूढ़ियों को बढ़ावा देते हैं। शिक्षकों का व्यवहार लड़के-लड़कियों के प्रति अलग होता है लड़कों को अधिक बोलने, नेतृत्व करने और गलती करने की छूट मिलती है, जबकि लड़कियों से शांत रहने, आज्ञाकारी होने और "लड़की जैसे" व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें अभी भी पितृसत्तात्मक हैं। इतिहास में मुख्यतः पुरुष नायकों का वर्णन होता है, विज्ञान में पुरुष वैज्ञानिकों को प्रमुखता दी जाती है, जबकि महिलाओं की उपलब्धियाँ या तो गायब होती हैं या बहुत कम जगह पाती हैं। खेलकूद, डिबेट, एनसीसी जैसी गतिविधियों में लड़कियों की भागीदारी कम रखी जाती है या उन्हें अलग और कम महत्वपूर्ण गतिविधियाँ दी जाती हैं।

शिक्षण संस्थानों में यौन उत्पीड़न की शिकायत तंत्र कमजोर या नाममात्र का होता है, जिससे लड़कियाँ असुरक्षित महसूस करती हैं। वर्दी, समय-सीमा और नियम भी अक्सर लड़कियों पर अधिक सख्त होते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण में लैंगिक संवेदनशीलता को अनिवार्य विषय नहीं बनाया गया है, इसलिए अधिकांश शिक्षक अपनी निजी पूर्वाग्रहों के साथ ही पढ़ाते हैं। प्रशासनिक स्तर पर महिला शिक्षकों और प्रिंसिपलों की संख्या बहुत कम है, जिससे नीति-निर्माण में महिला दृष्टिकोण शामिल नहीं होता। परिणामस्वरूप शिक्षा संस्थान लैंगिक समानता सिखाने की बजाय मौजूदा असमानता को पुनरुत्पादित करते रहते हैं। जब तक शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सुधार, समान अवसर और सख्त उत्पीड़न-निवारण तंत्र नहीं बनाया जाएगा, शिक्षा संस्थानों में लैंगिक संवेदनशीलता केवल घोषणा बनकर रह जाएगी।

## 3. पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति की कमी

भारत के अधिकांश स्कूल-कॉलेजों का पाठ्यक्रम आज भी 50-60 साल पुरानी सोच पर टिका है। किताबों में माँ रसोई में खाना बना रही है, पिता अखबार पढ़ रहे हैं, डॉक्टर और इंजीनियर पुरुष हैं, नर्स और टीचर महिला। बच्चे यही देखकर बड़े होते हैं और यही सच मान लेते हैं। लैंगिक समानता, सहमति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, घरेलू काम का बराबर बँटवारा जैसे विषय पाठ्यक्रम में या तो गायब हैं या एक छोटे से बॉक्स में "वैकल्पिक" लिखकर टाल दिए गए हैं। शिक्षण पद्धति भी पूरी तरह शिक्षक-केंद्रित है। कक्षा में लड़कियों से कम सवाल पूछे जाते हैं, उनके जवाब को जल्दी काट दिया जाता है, जबकि लड़कों को बार-बार मौका और प्रशंसा मिलती है। परिणाम यह होता है कि दसवीं-बारहवीं तक आते-आते लड़कियाँ खुद को "कम समझदार" मानने लगती हैं। विज्ञान और गणित जैसे विषयों में उनका आत्मविश्वास जानबूझकर या अनजाने में तोड़ दिया जाता है।

शिक्षक खुद लैंगिक संवेदनशीलता पर ट्रेनिंग नहीं लेते। उन्हें यह भी नहीं सिखाया जाता कि "लड़के रोते नहीं" या "लड़कियाँ लड़ाई नहीं करती" जैसे वाक्य कितना नुकसान पहुँचाते हैं। नतीजा यह है कि स्कूल वह जगह बन जाता है जहाँ बच्चे घर से लाए पूर्वाग्रह को और मजबूत करके लौटते हैं। जब पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति ही लिंग-आधारित भूमिकाओं को बार-बार दोहराते रहें तो लैंगिक संवेदनशीलता की कोई भी कार्यशाला या नीति ऊपरी सतह पर तैरती रह जाती है। बच्चे का दिमाग बदलने का सबसे सशक्त मौका स्कूल में ही गँवाया जा रहा है।

## 4. डिजिटल युग की चुनौतियाँ

आज की पीढ़ी डिजिटल दुनिया में इतनी घुल-मिल गई है कि सुबह की शुरुआत ही स्क्रीन से होती है। बच्चे फोन या टैबलेट पर घंटों बिताते हैं, जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक या यूट्यूब पर कंटेंट अक्सर लैंगिक रूढ़ियों को बढ़ावा देता है। लड़कियों को मुख्य रूप से सौंदर्य, फैशन या रोमांटिक भूमिकाओं में दिखाया जाता है, जबकि लड़कों को आक्रामक या प्रमुख चित्रित किया जाता है। इस तरह का कंटेंट बच्चों के मन में लिंग-आधारित पूर्वाग्रहों को गहराई से स्थापित कर देता है, जिससे वे वास्तविक जीवन में समानता की बजाय असमानता को सामान्य मानने लगते हैं।

ऑनलाइन गेमिंग और चैट रूम में स्थिति और बदतर है। वहाँ लड़कियों को अक्सर सेक्सिस्ट कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, जैसे "लड़की हो तो हार जाओगी" या "तुम्हारी जगह किचन में है"। ये टिप्पणियाँ न केवल आत्मविश्वास तोड़ती हैं बल्कि लड़कों को भी गलत व्यवहार सिखाती हैं। इससे ज्यादा चिंताजनक है इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध पोर्नोग्राफी, जो 10-12 साल के बच्चों तक पहुँच जाती है। इसमें सहमति, सम्मान और स्वस्थ संबंधों की कोई अवधारणा नहीं होती, जिससे युवा मन में लैंगिकता की विकृत समझ विकसित होती है। परिणामस्वरूप, वे ऑफलाइन दुनिया में भी वैसा ही व्यवहार अपनाते हैं, जैसे उत्पीड़न या वस्तुकरण। शिक्षा संस्थानों में लैंगिक संवेदनशीलता पर जोर दिया जाता है, लेकिन डिजिटल चुनौतियों को नजरअंदाज किया जाता है। शिक्षकों की ट्रेनिंग में साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, रिवेज पोर्न या बॉडी शेमिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। अभिभावक भी अक्सर तकनीकी रूप से पिछड़े होते हैं और बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर नहीं रख पाते। लड़कियाँ जब ट्रोलिंग

या हैरासमेंट की शिकार होती हैं, तो वे चुप रह जाती हैं क्योंकि घर में शिकायत करने पर फोन छीनने या सजा का डर रहता है। वहीं, लड़के ऑनलाइन देखी गई हिंसा को स्कूल या दोस्तों के बीच दोहराते हैं, जिससे लैंगिक असमानता की जड़ें और मजबूत होती हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म की नीतियाँ भी अपर्याप्त हैं। हालांकि कुछ कंपनियाँ लैंगिक संवेदनशीलता की बात करती हैं, लेकिन उल्लंघनों पर कार्रवाई धीमी और अप्रभावी होती है। एल्गोरिदम अक्सर सेक्सिस्ट कंटेंट को प्रमोट करते हैं क्योंकि वह अधिक एंगेजमेंट लाता है। नतीजतन, जो बच्चे सबसे ज्यादा डिजिटल रूप से सक्रिय हैं, वे ही लैंगिक पूर्वाग्रहों से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब डिजिटल लिटरेसी को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए। स्कूलों में ऑनलाइन संवेदनशीलता पर वर्कशॉप्स, अभिभावकों के लिए गाइडेंस सेशन और पाठ्यक्रम में डिजिटल नैतिकता शामिल की जाए। शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाए कि वे बच्चों को सुरक्षित ब्राउजिंग सिखाएँ और पूर्वाग्रहों को चुनौती दें। सरकार और प्लेटफॉर्म को सख्त नियम लागू करने चाहिए, जैसे कंटेंट मॉडरेशन और उम्र-आधारित फिल्टर्स। बिना इन बदलावों के, स्कूली प्रयास व्यर्थ साबित होंगे और डिजिटल युग लैंगिक समानता की बजाय असमानता को बढ़ावा देता रहेगा।

## 5. संस्थागत प्रतिरोध

जब कभी लैंगिक संवेदनशीलता को गंभीरता से लागू करने की बात होती है, सबसे बड़ा रोड़ा संस्थानों का अपना प्रतिरोध होता है। स्कूल प्रबंधन, यूनिवर्सिटी प्रशासन, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी इसे "जरूरी लेकिन गौण" मुद्दा मानते हैं। बजट में इसका हिस्सा न के बराबर, ट्रेनिंग के लिए समय नहीं, और जिम्मेदारी किसी एक "महिला सेल" पर डालकर सब निश्चित। वरिष्ठ अधिकारी और प्रिंसिपल ज्यादातर पुरुष होते हैं जो खुद पितृसत्तात्मक सोच में बड़े हुए हैं। उनके लिए लैंगिक संवेदनशीलता का मतलब है "अपने विशेषाधिकार पर सवाल उठाना"। इसलिए वे इसे टालते हैं, कम महत्व देते हैं या सिर्फ कागज पर पूरा कर देते हैं। शिक्षक यूनियन भी विरोध करती हैं क्योंकि नई ट्रेनिंग का मतलब अतिरिक्त काम।

यौन उत्पीड़न की शिकायतें आने पर संस्थान सबसे पहले पीड़िता को ही चुप कराने या उसका चरित्रहनन करने में जुट जाते हैं, ताकि "संस्थान की इज्जत" बचे। इससे साफ संदेश जाता है कि लैंगिक संवेदनशीलता केवल दिखावे के लिए है। जब ऊपर से ही प्रतिरोध हो, तो नीचे के शिक्षक और कर्मचारी इसे गंभीरता से कैसे लेंगे? परिणामस्वरूप सारी नीतियाँ, कमेटीयों और दिशा-निर्देश कागजी शेर बनकर रह जाते हैं। जब तक संस्थागत नेतृत्व में जवाबदेही और इच्छाशक्ति नहीं आएगी, लैंगिक संवेदनशीलता स्कूल-कॉलेजों में केवल सेमिनार और पोस्टर तक सीमित रहेगी।

## प्रभावी पहलें

चुनौतियों के बावजूद, कई सफल पहलें अपनाई जा रही हैं जो लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देती हैं :-

### 1. नीतिगत सुधार

नीतिगत सुधार लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का एक मजबूत आधार बनाते हैं, क्योंकि ये कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को बदलकर समाज में समानता की भावना पैदा करते हैं। जब सरकारें लैंगिक समानता को प्राथमिकता देती हैं, तो इसका असर हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, एक महिला जो कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करती है, या एक लड़का जो घरेलू जिम्मेदारियों को साझा करना सीखता है। उदाहरण के लिए, भारत में लैंगिक समावेशी नीतियाँ जैसे शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस, जो स्कूलों में लिंग-आधारित भेदभाव को रोकती हैं, लोगों को अपनी पहचान के साथ जीने की आजादी देती हैं। ये सुधार न केवल नियम बनाते हैं बल्कि लोगों के मन में विश्वास जगाते हैं कि बदलाव संभव है।

नीतियों में लैंगिक संवेदनशीलता को शामिल करने से संस्थानों में जवाबदेही बढ़ती है। जैसे, यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए पॉस्को एक्ट या कार्यस्थल पर लैंगिक समानता के लिए मातृत्व अवकाश नीतियाँ, ये सब व्यक्तियों को सशक्त बनाती हैं। एक शिक्षक जो ऐसी नीतियों से प्रभावित होता है, वह कक्षा में अधिक निष्पक्ष हो जाता है, जिससे छात्रों में सम्मान की भावना विकसित होती है। हालांकि, इन सुधारों को लागू करने में चुनौतियाँ हैं, लेकिन जब ये सफल होते हैं, तो समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, पुरुषों में सहानुभूति आती है, और समग्र रूप से परिवार मजबूत होते हैं। नीतिगत बदलाव लोगों के दैनिक जीवन को छूते हैं, एक लड़की जो स्कूल में सुरक्षित महसूस करती है, वह बेहतर पढ़ाई करती है, एक पुरुष जो समान वेतन नीति से लाभान्वित होता है, वह घर में बराबरी सिखाता है। ये सुधार केवल कागज पर नहीं रहते, बल्कि भावनात्मक स्तर पर लोगों को जोड़ते हैं, पूर्वाग्रहों को तोड़ते हैं और एक न्यायपूर्ण समाज की नींव रखते हैं। जब नीतियाँ लैंगिक संवेदनशील होती हैं, तो हर व्यक्ति अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर पाता है, जिससे सामूहिक प्रगति होती है।

### 2. शिक्षक प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ

शिक्षक प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का सबसे व्यक्तिगत और प्रभावी तरीका हैं, क्योंकि ये शिक्षकों के मन को बदलकर छात्रों के जीवन को छूते हैं। एक शिक्षक जो पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है, वह कक्षा में हर बच्चे को समान अवसर देता है, लड़कियों को विज्ञान में प्रोत्साहित करता है, लड़कों को भावनाएँ व्यक्त करने की अनुमति देता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसे एनसीईआरटी की वर्कशॉप्स, शिक्षकों को अपनी खुद की सोच पर सवाल उठाने का मौका देते हैं, जिससे वे अधिक

मउचंजीमजपब बनते हैं।

कार्यशालाओं में रोल-प्ले, चर्चाएँ और केस स्टडीज के माध्यम से शिक्षक सीखते हैं कि कैसे भाषा और व्यवहार लैंगिक असमानता को बढ़ावा दे सकते हैं। उदाहरणस्वरूप, "लड़के मजबूत होते हैं" जैसे वाक्यों को चुनौती देकर वे छात्रों में आत्मविश्वास जगाते हैं। ये पहले शिक्षकों को न केवल ज्ञान देती हैं बल्कि भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं, ताकि वे छात्रों के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करें। परिणामस्वरूप, छात्र घर लौटकर परिवार में समानता की बातें करते हैं, जो समाज में फैलती है। शिक्षक प्रशिक्षण का असर गहरा होता है, एक प्रशिक्षित शिक्षक सैकड़ों छात्रों के जीवन को प्रभावित करता है, उन्हें पूर्वाग्रहों से मुक्त करता है। ये कार्यशालाएँ शिक्षकों को अपनी कमजोरियों का सामना करने का साहस देती हैं, जिससे वे बेहतर इंसान बनते हैं। जब शिक्षक संवेदनशील होते हैं, तो छात्रों में सहानुभूति, सम्मान और बराबरी की भावना जन्म लेती है। ये पहले चुनौतियों के बीच उम्मीद की किरण हैं, क्योंकि ये लोगों के दिलों को बदलती हैं, न कि सिर्फ नियम। अंततः, ऐसे प्रशिक्षण समाज को अधिक मानवीय बनाते हैं, जहाँ हर व्यक्ति अपनी पहचान के साथ फल-फूल सके।

### 3. पाठ्यक्रम में समावेश

पाठ्यक्रम में लैंगिक संवेदनशीलता का समावेश छात्रों के मन को शुरुआत से ही आकार देता है, जिससे वे एक समान समाज का हिस्सा बनते हैं। जब किताबों में महिलाओं की उपलब्धियाँ, जैसे मैरी क्यूरी या कल्पना चावला की कहानियाँ, प्रमुखता से शामिल की जाती हैं, तो लड़कियाँ खुद को सशक्त महसूस करती हैं और लड़के सम्मान सीखते हैं। ये बदलाव पाठ्यक्रम को अधिक मानवीय बनाते हैं, जहाँ हर बच्चा अपनी भावनाओं को समझता है और दूसरों की सराहना करता है। पाठ्यक्रम सुधार में विषय जैसे सहमति, घरेलू बराबरी और लिंग-आधारित हिंसा पर अध्याय जोड़े जाते हैं, जो छात्रों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों से जोड़ते हैं। इससे वे न केवल पढ़ते हैं बल्कि महसूस करते हैं कि असमानता कैसे लोगों को दुख पहुँचाती है। उदाहरण के लिए, सीबीएसई के नए मॉड्यूल में लैंगिक समानता को अनिवार्य बनाना शिक्षकों और छात्रों दोनों को प्रभावित करता है। ये समावेश छात्रों में मउचंजील विकसित करते हैं, ताकि वे बड़े होकर पूर्वाग्रहों को न दोहराएँ।

पाठ्यक्रम का यह बदलाव गहरा भावनात्मक प्रभाव डालता है, एक बच्चा जो किताब से सीखता है कि घर का काम सबका है, वह परिवार में मदद करता है एक किशोर जो हिंसा के खिलाफ पढ़ता है, वह दोस्तों में सकारात्मक बदलाव लाता है। ये पहले चुनौतियों को पार करके समाज को मानवीय बनाती हैं, जहाँ हर व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित रहती है। जब पाठ्यक्रम संवेदनशील होता है, तो शिक्षा न सिर्फ ज्ञान देती है बल्कि दिलों को जोड़ती है, पूर्वाग्रहों को मिटाती है और एक बेहतर दुनिया की नींव रखती है। अंततः, ऐसे समावेश छात्रों को सशक्त बनाते हैं, ताकि वे जीवन में समानता को जी सकें।

### 4. कैंपस स्तर पर पहल

कैंपस स्तर पर लैंगिक संवेदनशीलता की पहलें छात्रों के दैनिक जीवन को छूती हैं, जहाँ वे अपनी पहचान और संबंधों को समझते हैं। जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्लब और सोसाइटीज लैंगिक समानता पर फोकस करती हैं, तो छात्र अधिक खुलकर बात करते हैं, एक लड़की जो डिबेट में हिस्सा लेती है, वह आत्मविश्वास महसूस करती है, जबकि एक लड़का जो वर्कशॉप में भावनाओं पर चर्चा करता है, वह सहानुभूति सीखता है। ये पहले, जैसे जेंडर इक्वलिटी सेल या अवेयरनेस कैंपेन, छात्रों को सुरक्षित स्पेस देती हैं जहाँ वे पूर्वाग्रहों पर सवाल उठा सकें।

कैंपस में एंटी-हैरासमेंट कमेटीयों और पीयर मेंटरिंग प्रोग्राम व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव लाते हैं। एक छात्रा जो उत्पीड़न की शिकायत करती है, उसे न्याय मिलने से विश्वास बढ़ता है, और पूरा कैंपस अधिक सम्मानजनक बनता है।

वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में छात्र खुद भाग लेते हैं, जिससे वे न केवल सीखते हैं बल्कि दूसरों को प्रभावित करते हैं। उदाहरणस्वरूप, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम छात्रों के मन में समानता की भावना जगाते हैं, जहाँ वे घर से लाए पूर्वाग्रहों को छोड़ते हैं। ये पहले भावनात्मक रूप से गहरी होती हैं, एक छात्र जो कैंपस इवेंट में लिंग-आधारित हिंसा पर बोलता है, वह अपने दोस्तों में बदलाव लाता है। जब कैंपस लीडरशिप महिलाओं को बढ़ावा देती है, तो छात्राएँ खुद को मजबूत महसूस करती हैं। ये प्रयास चुनौतियों के बीच उम्मीद देते हैं, क्योंकि वे छात्रों के दिलों को बदलते हैं, समाज को अधिक मानवीय बनाते हैं। अंततः, कैंपस स्तर की पहलें युवाओं को सशक्त बनाती हैं, ताकि वे जीवन में बराबरी को अपनाएँ और फैलाएँ।

### 5. डिजिटल और सामुदायिक पहल

डिजिटल और सामुदायिक पहलें लैंगिक संवेदनशीलता को आम लोगों तक पहुँचाती हैं, जहाँ वे अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करते हैं। सोशल मीडिया कैंपेन जैसे #MeToo या #GenderEquality लोगों को अपनी कहानियाँ साझा करने का मौका देते हैं, एक महिला जो ऑनलाइन उत्पीड़न की बात करती है, वह दूसरों को साहस देती है, जबकि पुरुष जो इन पोस्ट्स पढ़ते हैं, वे अपनी सोच बदलते हैं। ये पहले डिजिटल दुनिया में पूर्वाग्रहों को चुनौती देती हैं, लोगों को जुड़ाव महसूस कराती हैं।

सामुदायिक स्तर पर एनजीओ और लोकल ग्रुप्स वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं, जहाँ परिवार और पड़ोसी मिलकर चर्चा करते हैं। एक माँ जो सामुदायिक मीटिंग में लिंग-आधारित भूमिकाओं पर बोलती है, वह घर में बराबरी सिखाती है। डिजिटल टूल्स जैसे ऐप्स और ऑनलाइन कोर्स, जैसे यूनेस्को के प्रोग्राम, लोगों को घर बैठे संवेदनशीलता सिखाते हैं, जिससे वे भावनात्मक रूप से

मजबूत होते हैं। भारत में प्रोजेक्ट्स जैसे “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” डिजिटल और कम्युनिटी को जोड़ते हैं, जहाँ वीडियो और मीटिंग्स से लोग प्रभावित होते हैं। ये पहलें गहरी भावनाएँ जगाती हैं, एक युवा जो ऑनलाइन कैंपेन में हिस्सा लेता है, वह दोस्तों में समानता फैलाता है। सामुदायिक इवेंट्स में लोग अपनी कमजोरियों को साझा करते हैं, जिससे बंधन मजबूत होते हैं। चुनौतियों के बावजूद, ये प्रयास समाज को मानवीय बनाते हैं, जहाँ हर व्यक्ति सम्मान पाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्मस एल्गोरिदम को संवेदनशील बनाकर असमानता कम करते हैं। अंततः, ये पहलें लोगों के दिलों को छूती हैं, एक बेहतर दुनिया बनाती हैं जहाँ समानता रोजमर्रा की हकीकत बने।

## 6. अनुसंधान और मूल्यांकन

अनुसंधान और मूल्यांकन लैंगिक संवेदनशीलता की पहलों को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि ये डेटा से लोगों के जीवन में बदलाव को मापते हैं। जब शोधकर्ता सर्वे और स्टडीज करते हैं, तो वे वास्तविक कहानियाँ सामने लाते हैं, एक छात्रा जो प्रोग्राम के बाद अधिक आत्मविश्वास महसूस करती है, वह आंकड़ों में जीवंत हो उठती है। ये मूल्यांकन पहलों की कमियों को उजागर करते हैं, ताकि वे अधिक प्रभावी बनें, लोगों को उम्मीद देते हैं। अनुसंधान में केस स्टडीज और इंटरव्यूज से पता चलता है कि लैंगिक ट्रेनिंग कैसे व्यवहार बदलती है। उदाहरणस्वरूप, यूएन की रिपोर्ट्स भारत में प्रोग्राम्स का मूल्यांकन करती हैं, जहाँ महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। ये स्टडीज भावनात्मक प्रभाव को मापती हैं, जैसे एक पुरुष जो शोध में हिस्सा लेता है, वह अपनी पूर्वाग्रहों को पहचानता है। मूल्यांकन टूल्स जैसे फीडबैक फॉर्मस और लॉन्ग-टर्म ट्रेकिंग पहलों को बेहतर बनाते हैं, संस्थानों में जवाबदेही लाते हैं।

ये प्रयास गहरे स्तर पर छूते हैं, एक शोधकर्ता जो डेटा इकट्ठा करता है, वह लोगों की भावनाओं को समझता है, समाज को अधिक मानवीय बनाता है। जब मूल्यांकन से पता चलता है कि प्रोग्राम सफल है, तो लोग प्रेरित होते हैं। चुनौतियों के बीच, अनुसंधान नई दिशाएँ देता है, जैसे डिजिटल प्रभाव का अध्ययन। अंततः, ये पहलें डेटा को दिल से जोड़ती हैं, लैंगिक संवेदनशीलता को स्थायी बनाती हैं, ताकि हर व्यक्ति समानता का अनुभव करे।

## निष्कर्ष

लैंगिक संवेदनशीलता कोई वैकल्पिक मुद्दा नहीं, बल्कि समावेशी समाज की आधारशिला है। चुनौतियाँ गंभीर हैं, किंतु सही पहलों से इन्हें दूर किया जा सकता है। शिक्षा जगत के वरिष्ठ प्रोफेसरों और नीति-निर्माताओं की जिम्मेदारी है कि वे लैंगिक संवेदनशील वातावरण का निर्माण करें। भविष्य में, यदि हम पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और नीतियों में लैंगिक दृष्टिकोण को मुख्यधारा बनाएँ, तो न केवल छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होगा। आइए, हम सभी मिलकर इस दिशा में कदम उठाएँ, क्योंकि लैंगिक समानता सबकी साझा जिम्मेदारी है।

**संदर्भ:**

1. Agarwal, N. (2022). *Gender issues in education*. Shipra Publications.
2. Bhatt, S., & Sharma, A. (2021). *Gender sensitivity and education*. Rawat Publications.
3. Chanana, K. (2019). *Gender and education in India: A reader*. Orient BlackSwan.
4. Desai, N., & Krishnaraj, M. (2020). *Women and society in India* (2nd ed.). Sage Texts.
5. Ghadially, R. (Ed.). (2021). *Women in Indian society: A reader*. Sage Publications India.
6. Govinda, R. (Ed.). (2020). *Gender equity in education: Policy and practice in India*. Oxford University Press.
7. Jain, S., & Singh, R. (2023). *Gender sensitization in schools: Concepts and strategies*. Anamika Publishers & Distributors.
8. Karlekar, M. (2019). *Education and gender*. National Institute of Open Schooling (NIOS), Ministry of Education, Government of India.
9. Manjrekar, N. (2021). *Gender and education: Critical perspectives*. Routledge India.
10. NCERT. (2022). *Gender studies: Textbook for Class XI & XII (Supplementary reading)*. National Council of Educational Research and Training.
11. Nayar, S., & Singh, R. (2020). *Gender school and society*. Vikas Publishing House.
12. Pandey, V. C. (2021). *Gender equality and women empowerment*. Isha Books.
13. Saxena, S., & Sharma, N. (2023). *Gender sensitization and education*. Neelkamal Publications.
14. Velaskar, P. (2021). *Gender and education in India: Sociological perspectives*. Rawat Publications.
15. NFHS-5 Report, Ministry of Health and Family Welfare, Gol.
16. UGC Saksham Report, 2013.
17. UNESCO Gender Equality in Education, 2020.
18. NCRB Crime in India Report, 2022.